

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(ग्रसाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 13 जून, 2002/23 ज्येष्ठ, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

ग्रधिसूचना

शिमला-171002, 10 जून, 2002

संख्या टी0पी0टी0-एफ (6)2/2000. — प्रारूप संशोधन निया, नामतः हिमाचल प्रदेश मोटरयान (प्रथम संशोधन) नियम, 2002, मोटरयान प्रधिनियम, 1988 की धारा 212 के उपबन्धों के अनुसरण में समसंस्थक अधिसूचना 4 अप्रैल, 2002 द्वारा इनसे सम्भाव्य प्रभावित व्यक्तियों से मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 के प्रधीन यथा अपेक्षित, इनकी प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमित्वत करने के लिए राजपव्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 6 मई, 2002 को प्रकाशित किए गए थे।

ग्रतः उक्त प्रारूप संशोधन के बारे में नियत श्रवधि के भीतर जनसाधारण से कोई आक्षेप श्रीर सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। ग्रतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटरयान ग्रिधिनियम, 1988 की धारा-212 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

प्रारूप नियम

- 1. संक्षिप्त नाम.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटरयान (प्रथम संशोधन) नियम, 2002 है।
 - (ii) ये राजपव में इनके अन्तिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. नियम 69-ख का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश मोटरयान नियम, 1999 के विद्यमान नियम 69-ख के स्थान पर, निम्निखत नियम रखा जाएगा, ग्रथान :--

69-ख. रजिस्ट्रोकरण चिन्ह के आबंदन के लिए विशेष रजिस्ट्रोकरण फीस.—केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 81 के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य में, सभी रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन आधिकारियों द्वारा मोटरयानों को निम्नलिखित रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के आबंदन के लिए, रजिस्ट्रीकरण फीस के अतिरिक्त विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित की जाएगी :—

		•
क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	विश <mark>ेव रजिस्ट्रीकर</mark> ण फीस
1.	0001	30,000/- रुपये (तीस हजार हपये) <mark>ड</mark> ़
2.	0002 से 0009 तक	25,000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये)
3.	0010 से 0100	15,000/- रुपये (पन्द्रह हजार रुपये)
4.	0101 से 9999	2,500/- हपये (दो हजार पांच सौ रुपये केवल) :
		_

परन्तु कम संख्या (1) से (3) के लिए विनिद्दिष्ट रिजस्ट्रीकरण चिन्ह, पहले आश्रो पहले पाओ के आधार पर आबंटित किए जाएंगे तथापि, जहां किसी विजिष्ट चिन्ह के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त किए जाते हैं, वहां उसे लाटरी के द्वारा आवंटित किया जाएगा:

परन्तु यह ग्रौर कि कम संख्या (4) के सामने विनिर्दिष्ट रिजस्ट्रीकरण चिन्ह की दशा में क्रम संख्या (1) के सामने विनिर्दिष्ट रिजस्ट्रीकरण चिन्ह में से किसी विशिष्ट रिजस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए मोटरयान के स्थामी द्वारा चत्रन उपग्रिशत किया जाता है केवल तभी विशेष रिजस्ट्रीकरण फीस प्रभावित की जाएगी ऐसा न होने पर वे चिन्ह कमानुसार/कालानुकप में पहले ग्राग्रो पहले पाग्रो के ग्राग्रार पर ग्राबंटित किए जाएंगे:

परन्तु यह ग्रौर कि यदि कोई मोटरयान दुर्घंटनाग्रस्त हो जाता है ग्रीर वीमा कम्पनी द्वारा सम्यक् रूप से पूर्ण क्षति प्रमाणित की जाती है, तो उक्त मोटरयान के स्वामी से नए यान हेतु उसी रिजस्ट्रीकरण विन्ह के लिए निहित फीस संदत्त करनी ग्रथेक्षित नहीं होगी : परन्तु यह श्रीर कि जिस्ट्रीकरण एवं ग्रनुजापन प्राधिकारी, उपयोग न किए गए चिन्हों को राज्य मरकार के स्वामित्व वाले यानों को, विशेष रजिस्टीकरण फीस प्रभारित किए विना, ग्रावंटित कर सकेगा।

आवेश द्वारा.

वी0 के0 वंस्ल, मचित

[Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-F(6) 2/2000, dated 10th June, 2002 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

9

.

Shimla-2, the 10th June, 2002

No. TPT-F(6)2/2000.—Whereas the draft amendment rules titled as the Himachal Pradesh Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2002 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) on the 6th May, 2002 vide notification of even number dated 4-4-2002 in pursuance of the provisions of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988, for inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby as required under section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 within a period of 30 days from the date of publication:

And, whereas, no objections/suggestions have been received from the general public within the stipulated period in respect of the said draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 212 of Motor Vehicles Act, 1988, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2002.
- (2) They shall come into force from the date of final publication in the official Gazette.
- 2. Substitution of Rule 69-B.—For the existing rule 69-B of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, the following rule shall be substituted, namely:—
- 69-B. Special Registration Fee for allotment of registration marks.— There shall be charged a Special Registration Fee, in addition to the registration fee, prescribed under rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, for allotment of the following registration marks to the motor vehicles by all Registering and licencing Authorities in the State of Himachal Pradesh:—

	Sl. No.	Registration Marks	Special Registration Fee
į.	(i) (ii) (iii) (iv)	0001 0002 to 0009 0010 to 0100 0101 to 9999	Rs. 30.000/- (Thirty thousand only) Rs. 25,000/- (Twenty five thousand only) Rs. 15,000/- (Fifteen thousand only) Rs. 2,500/- (Two thousand and five hundred only):

Provided that registration marks specified against serial No. (i) to (iii) shall be allotted on first come first serve basis. However, where more than one application is received for a particular number, the same shall be allotted by Draw of Lots:

Provided further that in the case of registration marks specified against Serial No. (iv), Special Registration Fee shall be charged only if choice is indicated by the owner of the motor vehicle for any particular registration marks out of the registration marks specified against Sl. No (iv), failing which these marks shall be allotted on first come first serve basis in seriatum/chronological order:

Provided further that in case any motor vehicle meets with an accident and is a total loss duly certified by the Insurance Company, the owner of the said vehicle shall be required to pay the Special Fee prescribed for the same registration number for a new vehicle:

Provided further that the Registration & Licencing Authority may allot unutilised specified marks to the motor vehicles owned by the State Government without charging any Special Registration Fee.

By order,

V. K. BANSAL, Secretary.